Maternity benefit schemes have been in-iroduccd for landless agricultural women workers.

Recently, a new scheme viz., NSAS (National Social Assistance Scheme) for the poor comprising old age pension <§> Rs. 75/- per month to destitutes over 65 years of age. family benefit of Rs. 5,000/-*g.* Rs. 10,000/- in case of natural and accidental death respectively of the primary bread winner of the household below poverty line and maternity benefit @ Rs. 300/- for the first two live births to poor women has been announced over and above the prevailing social security programmes ran by the State Governments.

Additionally Government is also contemplating to formulate and introduce seen a comprehensive Central Legislation to provide for health, safety & Welfare of agricultural workers.

झरिया कोयला खानों में आग को नियंत्रित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही किया जाना

794 **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि॰ की कुछ कोयला खानों में पिछले सात दशकों से आग लगी हुई है, जैसा कि 24 जुलाई, 1995 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अग्नि-नियंत्रण के संबंध में विश्व बैंक के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र में पहली बार कोयला क्षेत्रों में आग की सूचना 1916 में प्राप्त हुई थी। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद उपयुक्त रूप में सर्वेक्षण कार्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कोयला क्षेत्र के विभिन्न भागों में 70 आगों के लगभग 17 किलो मीटर के क्षेत्र में फैलने संबंधी क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया था। इस संबंध में किए गए निरन्तर प्रयासों से 9 आगों को पूर्णतया बुझा लिया गया है और अभी तक उनका परिसमापन कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) झरिया कोयला अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत, जोकि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, झरिया कोयला क्षेत्र आगों से संबंधित एक तैदानिक अध्ययन को जून, 1996 में पूरा कर लिया गया है। अंतिम रिपोर्ट को तैयार किए जाने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Upgradation and Modernisation of Public Sector Steel Plants

795. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the Government Policy regarding upgradalion of technology and moderni sation of existing public sector steel plants;

(b) whether the long pendency in the modernisation of Indian Iron and Steel Company (IISCO) $_0$f Burnpur, West Bengal, which is since then referred to BIFR has been agitating the trade union movement and Government of West bengal, and

(c) the steps taken by Government to modernise the IISCO plant and what is its present status?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) Assessment of the need for upgradation of technology and modernisation is made on a number of factors such as technological obsolescence, overcoming production bottlenecks, improving plant and equipment health for optimum utilisation of capacity, improving productivity and enhancing quality of products, improving yield, conserving energy, economising cost of production, improving the techno-economics, abating environmental pollution etc.

(b) Yes, Sir.